

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]
No. 104]

दिल्ली, शुक्रवार, जून 15, 2012/ज्येष्ठ 25, 1934
DELHI, FRIDAY, JUNE 15, 2012/JYAISTHA 25, 1934

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 63
[N.C.T.D. No. 63

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय एवं मुख्य पंजीकार (जन्म व मृत्यु)

अधिसूचना

दिल्ली, 15 जून, 2012

सं. फा. 13(2)/जी.शा./अ.स.नि./2012/3225.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 (1969 का अधिनियम सं. 18) की धारा 4 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निम्नलिखित अधिकारियों को मुख्य पंजीकार के पर्यवेक्षण व निर्देशन के अधीन उनके ऐसे कार्यों को सम्पन्न करने के लिए जो कि वह इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए समय-समय पर सम्पन्न करने के लिए उन्हें प्राधिकृत करें, सहर्ष नियुक्त करते हैं :—

निगम का नाम	नामोदिष्ट अधिकारी	सिविल पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत नामोदिष्ट अधिकारी
दक्षिण दिल्ली नगर निगम	निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रभारी अधिकारी, जीवनांक	अतिरिक्त मुख्य पंजीकार सहायक मुख्य पंजीकार
उत्तरी दिल्ली नगर निगम	निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रभारी अधिकारी, जीवनांक	अतिरिक्त मुख्य पंजीकार सहायक मुख्य पंजीकार
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	निगम स्वास्थ्य अधिकारी प्रभारी अधिकारी, जीवनांक	अतिरिक्त मुख्य पंजीकार सहायक मुख्य पंजीकार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश व उनके नाम से,

डी. एम. सपोलिया, प्रधान सचिव (योजना)

**DIRECTORATE OF ECONOMICS AND STATISTICS AND OFFICE OF THE CHIEF REGISTRAR
(BIRTHS AND DEATHS)**

NOTIFICATION

Delhi, the 15th June, 2012

No. F. 13(2)/VS/DES/2012/3225.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 4 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969 (Act No. 18 of 1969), the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi is pleased to appoint the following officers as Additional Chief Registrar and Assistant Chief Registrar, for purpose of discharging under the superintendence and directions of the Chief Registrar, such of his functions as he may, from time to time authorise them to discharge for the purpose of the said Act :—

Name of Corporation	Designated Officer	Designation under Civil Registration System
South Delhi M. C.	Municipal Health Officer Office Incharge Vital Statistics	Additional Chief Registrar Assistant Chief Registrar
North Delhi M. C.	Municipal Health Officer Office Incharge Vital Statistics	Additional Chief Registrar Assistant Chief Registrar
East Delhi M. C.	Municipal Health Officer Office Incharge Vital Statistics	Additional Chief Registrar Assistant Chief Registrar

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

D. M. SPOLIA, Pr. Secy.(Plg.)

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 15 जून, 2012

सं. फा. 3(3)/वित्त (राज. -1)/2012-13/डीएस-III/452.—केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 74) की धारा 13 की उप-धारा (3) तथा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस आशय के लिए सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली) नियमावली, 2005 में आगे संशोधन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियमावली

1. सक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली) (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. नियम 4 का संशोधन.—केन्द्रीय बिक्री कर (दिल्ली) नियमावली, 2005 (जिसे इसके पश्चात् मुख्य नियमावली कहा गया है) के नियम 4 में परन्तुक के पश्चात् तथा स्पष्टीकरण से पहले निम्नलिखित परन्तुक को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

“आगे उपबंध है कि आयुक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन पंजीकृत किसी व्यापारी या वर्ग या व्यापारियों के वर्ग या सभी व्यापारियों से विशेष या सामान्य आदेश से यथा अधिसूचित उसके द्वारा निर्धारित तरीके से इलैक्ट्रॉनिक्स रूप से सामंजस्य विवरण भरने के लिए कह सकता है :

यह भी उपबंध है कि इलैक्ट्रॉनिक रूप से सामंजस्य विवरणी भरने वाला व्यापारी इस विवरणी की एक हार्ड कॉपी भी घोषणा (ओं) या प्रमाण-पत्र (त्रों) के साथ भेजेगा यदि आयुक्त ने इसकी छूट प्रदान नहीं की है ।”

3. नियम 7 का संशोधन.—मुख्य नियमावली के नियम 7 के उप-नियम (1) में परन्तुक को हटाया जाएगा ।

4. नियम 8क का सन्निवेशन.—मुख्य नियमावली के नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

“8क. इस नियमावली में कुछ भी विपरीत होते हुए आयुक्त, किसी व्यापारी या वर्ग या व्यापारियों के वर्ग या धारा 7 के अधीन पंजीकृत सभी व्यापारियों को केन्द्रीय नियमावली के नियम 12 में निर्धारित घोषणा या प्रमाण-पत्र फार्मों के लिए इलैक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार एवं कर विभाग, दिल्ली की वेबसाइट के माध्यम से उसके द्वारा जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तरीके से तथा शर्तों के अनुसार आवेदन करने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कह सकता है ।

FINANCE (REVENUE-I) DEPARTMENT

NOTIFICATIONS

Delhi, the 15th June, 2012

No. F. 3(3)/Fin (Rev-I)/2012-13/DS-III/452.—In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of Section 13 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No. 74 of 1956), and all other powers enabling it in this behalf, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, makes the following rules further to amend the Central Sales Tax (Delhi) Rules, 2005, namely :—

RULES

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Sales Tax (Delhi) (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 4.—In the Central Sales Tax (Delhi) Rules, 2005, (hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 4, after the Proviso and before the explanation, the following provisos shall be inserted, namely :—

“Provided further that the Commissioner may require a dealer or class or classes of dealers or all dealers, registered under Section 7 of the Act, as may be notified by him by special or general order, to file the reconciliation return electronically in the manner prescribed by him :

Provided also that the dealers filing the reconciliation return electronically shall also file a hardcopy of such return along with the declaration(s) or certificate(s) unless exempted by the Commissioner.”

3. Amendment of rule 7.—In the principal Rules, in rule 7, in sub-rule (1), the proviso shall be omitted.

4. Insertion of rule 8A.—In the principal Rules, after rule 8, the following shall be inserted, namely :—

“8A. Notwithstanding anything contained to the contrary in these rules, the Commissioner may require a dealer or class or classes of dealers or all dealers, registered under Section 7 of the Act, as may be notified by him by special or general order, to apply and obtain the declaration or certificate Forms prescribed under rule 12 of the Central Rules, electronically through the website of the Department of Trade and Taxes, Delhi, in the manner and subject to the conditions specified in the notification issued by him :

Provided that no fee shall be payable by the dealer/dealers for such Forms downloaded from the website.”

सं. फा. 10(4)/वित्त (राज.-1)/2012-13/डीएस-III/453.—दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आरौ संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जाएगा ।

(2) ये दिल्ली सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. नियम 152 का संशोधन.—दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 152 में उप-नियम (1) के खंड (i) में तालिका के तृतीय कॉलम में “250 प्रतिशत” अंकों एवं शब्दों के स्थान पर “300 प्रतिशत” अंकों एवं शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

एस. के. कामरा, उप-सचिव-III (वित्त)

No. F. 10(4)/Fin. (Rev.-I)/2012-13/DS-III/453.—In exercise of the powers conferred by Section 81 of the Delhi Excise Act, 2009 (Delhi Act 10 of 2010), the Government of National Capital Territory of Delhi hereby makes the rules further to amend the Delhi Excise Rules, 2010, as following, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Delhi Excise (Third Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment of rule 152.—In the Delhi Excise Rules, 2010, in rule 152, in sub-rule (1), in clause (i) in the third column of the table for the figures and words “250 per cent”, the Figures and words “300 per cent” shall be substituted.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the
National Capital Territory of Delhi,

S. K. KAMRA, Dy. Secy.-III (Finance)

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग

अधिसूचनाएं

दिल्ली, 15 जून, 2012

सं. फा. 14(4)/एलए-2012/Cons2law/71.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 15 जून, 2012 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2012

(2012 का दिल्ली अधिनियम 07)

(6 जून, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[15 जून, 2012]

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरेसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जाएगा।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह उस तारीख से लागू होगा जैसा सरकार, सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. धारा 2 का संशोधन.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) (इसके बाद “मूल अधिनियम” के रूप में संदर्भित) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (घ) में उप-खंड (vii) के पश्चात् इसके अंत में आई व्याख्या से पूर्व निम्नलिखित परन्तुक सन्निविष्ट किए जाएंगे, अर्थात् :—

“शर्त यह है कि 3 जून, 2012 से प्रभावी होने वाले पेट्रोल के मूल्य (केन्द्र सरकार द्वारा उस पर वसूले कर एवं लैवी सहित) में वृद्धि के बराबर राशि, दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ होने की तिथि को या बाद की ऐसी तिथि तक, जो सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निदेश देती है या यदि पेट्रोल का मूल्य 3 जून, 2012 से पहले के विक्रय मूल्य से कम हो जाता है, जो भी पहले हो, बेचे गए पेट्रोल के विक्रय मूल्य का भाग नहीं होगा :

आगे शर्त यह है कि यदि पेट्रोल का मूल्य 3 जून, 2012 को प्रचलित मूल्य से अधिक पुनः बढ़ता है तो पूर्वोक्त परन्तुक पर इस प्रकार की आगामी वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आगे यह भी शर्त है कि यदि पेट्रोल के मूल्य में गिरावट आती है लेकिन 3 जून, 2012 से पूर्व प्रचलित मूल्य से अधिक रहता है, तो पूर्वोक्त परन्तुक का शेष बढ़ोतरी की सीमा तक प्रभाव पड़ेगा।

शर्त यह भी है कि उपभोक्ताओं तक लाभ पहुंचने तक पूर्वोक्त परन्तुक का प्रभाव नहीं होगा।”

DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATIONS

Delhi, the 15th June, 2012

No. F. 14(4)/LA-2012/Cons2law/71.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 15th June, 2012 and is hereby published for general information :—

“THE DELHI VALUE ADDED TAX (THIRD AMENDMENT) ACT, 2012

(DELHI ACT 07 OF 2012)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 6th June, 2012)

[15th June, 2012]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Amendment of section 2.—In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as the 'principal Act'), in Section 2, in sub-section (1), in clause (zd), after sub-clause (vii), before the Explanation occurring at the end thereof, the following provisos shall be inserted, namely :

"Provided that an amount equal to the increase in the price of petrol (including the duties and levies charged thereon by the Central Government), taking effect from the 3rd June, 2012 shall not form part of the sale price of petrol sold on or after the date of the commencement of the Delhi Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2012 till such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, direct or if the price of petrol falls below the sale price prior to 3rd June, 2012, whichever is earlier :

Provided further that if the price of petrol further increases from the level of price as on 3rd June, 2012, the aforesaid proviso shall not have any effect on such further increase :

Provided also, that if the price of petrol declines but remains above the price prevailing prior to 3rd June, 2012, the aforesaid proviso shall have effect to the extent of the remaining increase :

Provided also that the aforesaid proviso shall not take effect till the benefit is passed on to the consumers."

सं. फा. 14(6)/एलए-2012/Cons2law/61.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उपराज्यपाल की सहमति दिनांक 15 जून, 2012 को प्राप्त कर ली है और इसके द्वारा जन साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012

(2012 का दिल्ली अधिनियम 06)

(6 जून, 2012 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[15 जून, 2012]

दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 को पुनः संशोधित करने के लिए एक अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को दिल्ली मूल्य संवर्धित कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

(2) यह संपूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विस्तारित होगा।

(3) यह सरकारी राजपत्र में अधिसूचना से सरकार द्वारा यथानियत तिथि को प्रभावी होगा।

शर्त यह है कि इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तिथियां नियत की जा सकेंगी।

2. धारा 2 का संशोधन.—दिल्ली मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2004 (2005 का दिल्ली अधिनियम 3) (इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" रूप में संदर्भित) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (य घ) में खंड (vii) के बाद और व्याख्या से पूर्व आए उपबंध हटाए जाएंगे।

3. धारा 9 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(i) उप-धारा (3) में आए शब्द तथा अंक "(4) तथा (6)" के स्थान पर शब्द तथा अंक "(4), (6) तथा (10)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ii) उप-धारा (9) के पश्चात् निम्नलिखित धारा सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(10) उप-धारा (1) में कुछ भी प्रतिकूल रहते हुए, जहां—

(क) किसी व्यापारी ने वस्तुएं (पूँजीगत वस्तुओं के अतिरिक्त) खरीदी हैं जिसके लिए इस धारा की उप-धारा (1) के अंतर्गत कर क्रेडिट उत्पन्न होता है; तथा

(ख) ऐसी वस्तुओं में से वस्तुएं या विनिर्मित वस्तुएं केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत बिक्री करके दिल्ली से निर्यात की जानी है,

कर क्रेडिट की राशि निर्धारित प्रतिशत से कम की जाएगी।"

2163 DG/12-2

4. धारा 10 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (3) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(ग) दिल्ली से निर्यात की गई वस्तुएं :—

(i) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 8 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार की गई बिक्री से; अथवा

(ii) पंजीकृत डीलर की किसी शाखा को या खेप एजेंट को की गई बिक्री से भिन्न;” ।

5. धारा 28 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 28 के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“28 यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कर अवधि के लिए उसके द्वारा प्रस्तुत की गई किसी विवरणी में कोई त्रुटि निकालता है, तो वह ऐसी त्रुटि को दूर करेगा और ऐसी कर अवधि के वर्ष के अगले वर्ष के भीतर संशोधित विवरणी प्रस्तुत करेगा :

शर्त यह है यदि त्रुटि के परिणामस्वरूप इस अधिनियम के अंतर्गत देय कर से कम कर भुगतान किया है तो वह शेष देय कर तथा उस पर ब्याज का भुगतान करेगा :

आगे यह भी शर्त है कि 2010-2011 की किसी कर अवधि से संबंधित विवरणियों को छोड़कर, जो वर्ष 2011-2012 में प्रस्तुत किए जाने के लिए सूचीबद्ध थी, वर्ष 2008-2009, 2009-2010 एवं 2010-2011 के लिए संशोधित विवरणी 31 दिसम्बर, 2012 तक प्रस्तुत की जानी अपेक्षित होगी ।” ।

6. धारा 36क का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 36क की उप-धारा (11) में शब्द “निर्धारित अवधि के भीतर” के पश्चात् और शब्द “आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति से” सन्निविष्ट किए जाएंगे ।

7. धारा 38 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 38 की उप-धारा (7) के खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ग) धारा 26 और धारा 27 के अंतर्गत विवरणियां प्रस्तुत करना; अथवा

(घ) केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत यथापेक्षित घोषणा पत्र या प्रमाण प्रपत्र प्रस्तुत करना;” ।

8. धारा 49 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 49 के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“49 यदि किसी विशेष वर्ष के संबंध में, किसी डीलर की सकल बिक्री साठ लाख रुपये या ऐसी यथानिर्धारित अन्य राशि से बढ़ जाती है, तो ऐसा डीलर आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति, परिपत्र तथा अवधि में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा,” ।

9. धारा 50 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 50 में—

(i) उप-धारा (2) के खंड (घ) में परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

“आगे शर्त यह है कि ऐसी संख्यात्मक शृंखला, आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति से और ऐसी तिथि से उसके द्वारा प्रदान की जा सकेगी ।”

(ii) उप-धारा (5) में,—

(क) खंड (घ) में निम्नलिखित परन्तुक जोड़े जाएंगे, अर्थात् :—

“शर्त यह है कि कोई डीलर अलग संख्यात्मक शृंखला, दिल्ली में एक कार्य स्थल से अधिक कार्य स्थल की स्थिति में या प्रत्येक उत्पाद के लिए यदि एक उत्पाद से अधिक उत्पादों का व्यापार करता है या दोनों की स्थिति में भिन्न-भिन्न कूटांक सहित या तो पहले या बाद में लगाकर बना सकता है ।

आगे शर्त यह है कि ऐसी संख्यात्मक शृंखला, आयुक्त द्वारा यथा अधिसूचित पद्धति से और ऐसी तिथि से उसके द्वारा प्रदान की जा सकेगी ।”

(ख) खंड (ड) में शब्द “प्रदान की गई सेवाएं, उस पर वसूल किए गए कर की राशि सहित” के स्थान पर शब्द “प्रदान की गई सेवाएं तथा उस पर वसूल किए गए कर की राशि का अलग से उल्लेख किया जाए” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

10. धारा 66 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 66 की उप-धारा (2) के खंड (क) में आए शब्द “अतिरिक्त” के स्थान पर शब्द “विशेष” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

11. धारा 70 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 70 में,—

(i) धारा (2) में आए शब्द “प्रपत्र का प्रयोग” के स्थान पर “उसके द्वारा यथा अधिसूचित ऐसी पद्धति में प्रपत्र का प्रयोग” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप-धारा (5) में आए शब्द “पाँच सौ” के स्थान पर शब्द “दस हजार” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

12. धारा 73 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 73 में उप-धारा (8) के पश्चात् निम्नलिखित सन्निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

“(9) इस धारा के प्रतिकूल कुछ भी रहते हुए सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अधिसूचना में यथा उल्लिखित ऐसी शर्तों तथा विनियमों के अधीन एक या अधिक सदस्यों को मिलाकर पीठ गठित कर सकती है,”

13. धारा 82 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 82 में,—

(i) धारा (1) के खंड (ख) में आए शब्दों “लागत लेखाकार” के पश्चात् शब्द “अथवा कंपनी सचिव” सन्निविष्ट किए जाएंगे;

(ii) उप-धारा (2) में,—

(क) मुख्य खंड में आए शब्द “सनदी लेखाकार” के स्थान पर शब्द “सनदी लेखाकार, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव” प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

(ख) खंड (ख) में शब्द “सनदी लेखाकार” के पश्चात् शब्द “अथवा कंपनी सचिव” सन्निविष्ट किए जाएंगे ।

14. धारा 86 का संशोधन.—मूल अधिनियम की धारा 86 में,—

(i) उप-धारा (18) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित की जाएगी :—

“(18) यदि कोई व्यापारी इस अधिनियम की धारा 18 के उपबधों के अनुपालन में विफल रहता है तो डीलर को दस हजार रुपये की राशि अर्थदंड के रूप में भुगतान करनी होगी,” ।

(ii) उप-धारा (19) में आए शब्द “ऐसी वस्तुओं पर देय कर की राशि” के स्थान पर शब्द “ऐसी वस्तुओं के मूल्य के एक रुपये में चालीस पैसा” प्रतिस्थापित किए जाएंगे ।

No. F. 14(6)/LA-2012/Cons2law/61.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on 15th June, 2012 and is hereby published for general information :—

“THE DELHI VALUE ADDED TAX (SECOND AMENDMENT) ACT, 2012 (DELHI ACT 06 OF 2010)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 6th June, 2012)

[15th June, 2012]

An Act to further amend the Delhi Value Added Tax Act, 2004.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third year of the Republic of India as follows :—

1. Short title, extent and commencement.—(1) This Act may be called the Delhi Value Added Tax (Second Amendment) Act, 2012.

(2) It extends to the whole of the National Capital Territory of Delhi.

(3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the Official Gazette, appoint :

Provided that different dates may be appointed for different provisions of this Act.

2. Amendment of Section 2.—In the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 3 of 2005) (hereinafter referred to as the ‘principal Act’), in Section 2, in sub-section (1), in clause (zd), the provisos occurring after clause (vii) and before the Explanation shall be omitted.

3. Amendment of Section 9.—In the principal Act, in Section 9,—

(i) in sub-section (3), for the word and figures “(4) and (6)”, the word and figures “(4), (6) and (10)” shall be substituted;

(ii) after sub-section (9), the following shall be inserted namely :—

“(10) Notwithstanding anything contained to the contrary in sub-section (1), where—

- (a) a dealer has purchased goods (other than capital goods) for which a tax credit arises under sub-section (1) of this section; and,
- (b) the goods or goods manufactured out of such goods are to be exported from Delhi by way of sale made under sub-section (1) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956.

The amount of the tax credit shall be reduced by the prescribed percentage.”.

4. Amendment of Section 10.—In the principal Act in Section 10, in sub-section (3) for clause (e) the following shall be substituted, namely :—

“(c) the goods are exported from Delhi,—

- (i) by way of a sale made as per the provisions of sub-section (1) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956; or
- (ii) other than by way of a sale, to a branch of the registered dealer or to a consignment agent;”.

5. Amendment of Section 28.—In the principal Act, for section 28 the following shall be substituted, namely :—

“28. If a person discovers a discrepancy in a return furnished by him for a tax period under this Act, he shall remove such discrepancy and furnish a revised return within the year following the year of such tax period :

Provided that if, as a result of the discrepancy, the person has paid less tax than was due under this Act, he shall, pay the tax owed and interest thereon :

Provided further that for the years 2008-2009, 2009-2010 and 2010-2011, except for those returns pertaining to any tax period of 2010-2011, which were scheduled to be furnished in the year 2011-2012, the revised return shall be required to be furnished by 31st December, 2012.”.

6. Amendment of Section 36A.—In the principal Act, in Section 36A, in sub-section (11), after the words “within the prescribed period” the words, “and in the manner as may be notified by the Commissioner” shall be inserted.

7. Amendment of Section 38.—In the principal Act, in Section 38, in sub-section (7), for clause (c), the following clauses shall be substituted, namely :—

“(c) furnish returns under Section 26 and Section 27; or

(d) furnish the declaration or certificate forms as required under Central Sales Tax Act, 1956.”.

8. Amendment of Section 49.—In the principal Act, for Section 49 the following shall be substituted, namely,—

“49. If, in respect of any particular year, the gross turnover of a dealer exceeds sixty lakh rupees or such other amount as may be prescribed, then, such dealer shall submit a report in such manner, form and period as may be notified by the Commissioner.”.

9. Amendment of Section 50.—In the principal Act in Section 50,—

- (i) in sub-section (2) in clause (d) after the proviso, the following proviso shall be added namely—

“Provided further that such numerical series may be granted by the Commissioner, in such manner and from such date as may be notified by him;”,

- (ii) in sub-section (5),—

- (a) in clause (d), the following provisos shall be added, namely :—

“Provided that a dealer may maintain separate numerical series, with distinct codes, either as prefix or suffix, for each place of business, in case the dealer has more than one place of business in Delhi or for each product in case he deals in more than one product or both :

Provided further that such numerical series may be granted by the Commissioner, in such manner and from such date as may be notified by him;”,

- (b) in clause (e), for the words "services provided, inclusive of amount of tax charged thereon", the words "services provided and the amount of tax charged thereon indicated separately" shall be Substituted.

10. Amendment of Section 66.—In the principal Act, in Section 66, in sub-section (2), in clause (a), for the word "Additional", the word "Special" shall be Substituted.

11. Amendment of Section 70.—In the principal Act, in Section 70,—

- (i) in sub-section (2), for the words "using the form", the words "using the form in such manner as may be notified by him" shall be substituted;
- (ii) in sub-section (5), for the words "five hundred", the words "ten thousand" shall be substituted.

12. Amendment of Section 73.—In the principal Act, in Section 73, after sub-section (8), the following shall be inserted, namely :—

"(9) Notwithstanding anything contained to the contrary in this Section, the Government, may, by a notification in the official Gazette, constitute benches comprising of one or more members, subject to such conditions and regulations as may be laid down in the notification,".

13. Amendment of Section 82.—In the principal Act, in Section 82,—

- (i) in sub-section (1), in clause (b), after the words "cost accountant" the words "or company secretary" shall, be inserted;
- (ii) in sub-section (2),—
- (a) in the main clause, for the words "chartered accountant", the words "chartered accountant, cost accountant, company secretary" shall be substituted; and
- (b) in clause (b), after the words "cost accountant", the words "or company secretary" shall be inserted.

14. Amendment of Section 86.—In the principal Act, in Section 86,—

- (i) for sub-section (18) the following shall be substitute, namely :—

"(18) If, any dealer fails to comply with the provisions of Section 49 of this Act, the dealer shall be liable to pay, by way of penalty, a sum of ten thousand rupees."; and

- (ii) in sub-section (19), for the words "the amount of tax payable on such goods", the words "forty paisa in a rupee for the value of such goods" shall be substituted.

सं. फा. 14(3)/एलए-2012/Cons2law/48.—उपराज्यपाल, दिल्ली की दिनांक 12 जून, 2012 को मिली अनुमति के पश्चात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जनसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :—

"दिल्ली विनियोग (संख्या-2) अधिनियम, 2012 (2012 का दिल्ली अधिनियम 05)

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा 4 जून, 2012 को यथा पारित)

[12 जून, 2012]

वर्ष 2012-13 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के त्रेसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त शीर्षक.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 2) अधिनियम, 2012 है ।

2. 33436,00,00,000रुपयों का वर्ष 2012-2013 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तैतीस हजार चार सौ छत्तीस करोड़ रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के संबंध में वर्ष 2012-2013 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी ।

2163 DG/12-3

3. विनियोजन.—इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के संबंध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जाएगी।

अनुसूची
(धाराएं 2 व 3 देखें)

(रुपये हजारों में)

मांग संख्या		सेवाएं एवं उद्देश्य		राशि इससे अधिक नहीं	
				संचित निधि पर भारित	जोड़
1	2	3	4	5	
1.	विधान मंडल	राजस्व	150500	6600	157100
2.	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1041320	96660	1138000
		पूंजी	"	"	"
3.	न्याय. प्रशासन	राजस्व	4185590	1273510	5459100
4.	वित्त	राजस्व	2224950	50	2225000
		पूंजी	330000	"	330000
5.	गृह	राजस्व	3224700	2800	3227500
6.	शिक्षा	राजस्व	45323250	3050	45326300
		पूंजी	3335000	"	3335000
7.	चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य	राजस्व	29327245	8255	29335500
		पूंजी	"	"	"
8.	समाज कल्याण	राजस्व	24984500	"	24984500
		पूंजी	15397000	"	15397000
9.	उद्योग	राजस्व	3153850	350	3154200
			585200	"	585200
10.	विकास	राजस्व	15165830	1570	15167400
		पूंजी	3129600	400	3130000
11.	शहरी विकास एवं लोक निर्माण	राजस्व	62553700	400	62554100
		पूंजी	71579100	"	71579100
	सार्वजनिक ऋण	राजस्व	"	33000000	33000000
		पूंजी	"	13000000	13000000
12.	ऋण	पूंजी	25000	"	25000
13.	पेंशन	राजस्व	1250000	"	1250000
जोड़			286966335	47393665	334360000 "

तरुन सहरावत, अतिरिक्त सचिव

No. F. 14(3)/LA-2012/Cons2law/48.—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 12th June, 2012 and is hereby published for general information :—

"THE DELHI APPROPRIATION (NO. 2) ACT, 2012
(DELHI ACT 05 OF 2012)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 4th June, 2012)

[12th June, 2012]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year, 2012-2013.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. Short title.—This Act may be called the Delhi Appropriation (No. 2) Act, 2012.

2. Issue of Rs. 33436,00,00,000 from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year, 2012-2013.—From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees thirty three thousand four hundred thirty six crore only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year, 2012-2013 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

3. Appropriation.—The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

SCHEDULE

[See Sections 2 and 3]

(Rs. in thousands

Sums Not Exceeding

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
1.	Legislative Assembly	Revenue	150500	6600	157100
2.	General Administrative	Revenue	1041320	96680	1138000
		Capital
3.	Administration of Justice	Revenue	4185590	1273510	5459100
4.	Finance	Revenue	2224950	50	2225000
		Capital	330000	..	330000
5.	Home	Revenue	3224700	2800	3227500
6.	Education	Revenue	45323250	3050	45326300
		Capital	3335000	..	3335000
7.	Medical and Public Health	Revenue	29327245	8255	29335500
		Capital
8.	Social Welfare	Revenue	24984500	..	24984500
		Capital	15397000	..	15397000
9.	Industries	Revenue	3153850	350	3154200
		Capital	585200	..	585200
10.	Development	Revenue	15165830	1570	15167400
		Capital	3129600	400	3130000
11.	Urban Development and	Revenue	62553700	400	62554100
	Public Works	Capital	71579100	..	71579100
	Public Debt	Revenue	..	33000000	33000000
		Capital	..	13000000	13000000
12.	Loans	Capital	25000	..	25000
13.	Pension	Revenue	1250000	..	1250000
Total			286966335	47393665	334360000"

TARUN SAHRAWAT, Addl. Secy.